अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/90/2019-20 **24 फरवरी, 2020**

सेवा में

श्री विनोद कुमार मंडल,
अवर सचिव/केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री दयाकिशन जोशी, एफ-104, गली न. 4 वेस्ट करावल नगर, पो. आ. करावलनगर, दिल्ली-110090 का 23.02.2020 का पत्र इस सचिवालय में 24.02.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने अपना बीपीएल कार्ड सं. 00772831906 अंकित कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में तैयार हो रहे आवासों के संबंध पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। चूंकि इनके पत्र की विषय-वस्तु आपके विभाग से संबंधित है अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्तक्षारी को सूचित करते हुए आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-
श्री दयाकिशन जोशी, एफ-104, गली न. 4 वेस्ट करावल नगर, पो. आ. करावलनगर, दिल्ली-110090-
कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

O/c
Narain Sgl
27/2/20

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 — प्रार्थना-पत्र

दिनांक 23/02/2020

1035
24/2/20

सेवा में,

श्रीमान माननीय केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी महोदयजी
उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार,
6, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली - 110011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं भिजवाने हेतु प्रार्थना-पत्र:-

महोदयजी,

सविनय निवेदन यह है कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें निम्न लिखित सूचनाएं RTI Act 2005 के तहत भिजवाने की कृपा करें। हम आपका यह उपकार जिन्दगी भर नहीं भूलेंगे। तथा सदा ही आपके आभारी रहेंगे।

1. भारतीय (प्रधानमंत्री) आवास योजना के तहत दिल्ली में कहाँ कहाँ पर तथा कितने-2 मकान तैयार हो चुके हैं या तैयार हो रहे हैं कृपया करके विस्तार पूर्वक सूचना भिजवाने की कृपा करें।
2. PMAY (CMAY) (EWS BPL) परिवारों के लिए क्या योजना है तथा इसके लिए किस तरह से APPLY करना होता है Registration कैसे होता है कृपया करके पूरी सूचना भिजवाने की कृपा करें।
3. (PMAY) (CMAY) (1 BHK, 2 BHK) किस तरह के मकान बनाये गये हैं तथा BPL परिवारों के लिए यह कितने रुपये में मिलेंगे क्या होता है कृपया पूरा Amount की जानकारी भी कृपया करें।

PMAY (CMAY) के मकान (फ्लैट) NBCC, HUDCO, DDA या कोई अन्य संस्था या Pvt Builders Real Estate या कोई अन्य संस्था क्या दिल्ली में कहाँ कहाँ पर बन चुके हैं या किन्हें दिया गया है या नहीं या बनाये जा रहे हैं।

5. PMAY (CMAY) के तहत EWS BPL परिवारों को कितने-कितने लोन LOAN क्या National Housing Bank, LIC Housing Finance तथा अन्य किस बैंक से कितना LOAN क्या कितने समय के लिए क्या किस ब्याज दर पे मिल जाता है पूरी जानकारी दिलवाने की कृपा करें।

6. PMAY (CMAY) BPL EWS परिवारों को खरीदने के लिए कितनी क्या किस प्रकार की क्या बैंकों से कितना [illegible] मिल जाता है क्या कितना वापस क्या बिना वापस करना होता है।

7. PMAY (CMAY) (आवास) हेतु APPLY Registration करने हेतु कौन कौन से क्या Months, Date, Year क्या इसके लिए क्या क्या Address Proof चाहिए होते हैं पूरी जानकारी दिलवाने की कृपा करें।

8. EWS BPL परिवारों को सरकारी बैंकों क्या सरकारी [illegible] क्या NH Bank & LIC Housing Finance द्वारा कितना Home LOAN क्या कितने Interest पर क्या कितने समय के लिए मिल जाता है या नहीं। पूरी सूचना दिलवाने की कृपा करें।

सार्वजनिक हित आपका यह उपकार जिन्दगी भर नहीं भूल पायेंगे। क्या हमेशा ही आपके आभारी रहेंगे।

(आपकी अति कृपा होगी)
EWS BPL Category
BPL Card No
077002831906

(प्रार्थी)
दयाकिशन [illegible]
H.No. F-104, Gali No 4
WEST KARAWAL NAGAR
P.O. KARAWAL NAGAR
DELHI-110090

13 हिन्दुस्तान
नई दिल्ली • सोमवार • 26 अगस्त 2019

आज का दिन 1914 में क्रांतिका...
से 50 माउजर औ...

देशभर में अटकी परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए मिल सकती है वित्तीय मदद

घर मिलने की राह आसान होगी

नई दिल्ली | एजेंसी

देशभर में अटकी अवासीय परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले लाखों घर खरीदारों को इस हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि रियल एस्टेट कंपनियों की नकदी किल्लत दूर करने और घर खरीदारों को उनका घर दिलाने के लिए इस हफ्ते वित्तीय मदद (स्ट्रेस फंड) की घोषणा हो सकती है।

इसके साथ ही निर्माणाधीन आवासीय परियोजना पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव की भी संभावना है। सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी घटाकर 12 से पांच फीसदी कर दिया था। साथ ही किफायती आवास परियोजनाओं पर जीएसटी आठ से घटाकर एक फीसदी कर दिया था। हालांकि इसके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई थी। इससे डेवलपर पर निर्माण की लागत बढ़ गई थी। वह इसका बोझ घर खरीदारों पर डालने लगे थे। हाल ही में वित्त मंत्री के साथ घर खरीदारों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। इसको देखते हुए निर्माणाधीन परियोजना पर जीएसटी दर में बदलाव करने की तैयारी है।

मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निर्माणाधीन आवासीय परियोजना पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी की जा सकती है। लेकिन इनपुट क्रेडिट का लाभ फिर से दिया जाएगा। इससे परियोजना की निर्माण लागत में कमी आएगी। इसका फायदा डेवलपर घर खरीदारों को देंगे।

220 प्रोजेक्ट में 1.74 लाख घर सात बड़े शहरों में अटके

1.18 लाख फ्लैट अटके हुए हैं सिर्फ एनसीआर में

1774 अरब कीमत है अटके प्रोजेक्ट की

2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य है सरकार का

इसलिए आई रियल एस्टेट में मंदी

प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इस सेक्टर में मंदी आने की वजह आपूर्ति बढ़ना और मांग में कमी आना है। 2012 में कई डेवलपर ने अपनी वित्तीय स्थिति को आंके बिना कई प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च किए बाद में उसे पूरा नहीं कर पाए। इससे खरीदारों का विश्वास डोला और बिक्री गिर गई।

28% घटी है घरों की बिक्री

ब्रोकरेज कंपनी एनारॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच साल के दौरान घरों के दाम में सात फीसदी का मामूली इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान इनकी मांग 28 फीसदी घटी है। इसी तरह घरों की आपूर्ति में इस दौरान 64 प्रतिशत की गिरावट आई है।

पांच लाख घर खरीदार प्रभावित

फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स के अनुसार, प्रॉजेक्ट्स में देरी से देशभर में पांच लाख से अधिक घर खरीदार प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा एनसीआर के हैं।

अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर

नारेडको अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि रियल्टी पर करों को तर्कसंगत बनाने और नकदी संकट दूर करने से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

नकदी किल्लत दूर करना जरूरी : अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने बताया कि सैकड़ो प्रोजेक्ट का काम नकदी संकट से रुका पड़ा या बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इससे रियल एस्टेट कंपनियों और घर खरीदारों दोनों का नुकसान हो रहा है। फंड की कमी से डेवलपर प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं पा रहे हैं। अगर इस सेक्टर में नकदी की समस्या दूर होती है तो घर खरीदारों को घर मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सस्ते कर्ज से बढ़ेगी मांग : वित्त मंत्री ने आवास वित्त कंपनियों को 20 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है। वहीं बैंकों को कर्ज रेपो रेट से जोड़ने को कहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कर्ज की उपलब्धता बढ़ेगी और लोन की ईएमआई घटेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना : बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को मिलेगा पुरस्कार

नई दिल्ली, 8 फरवरी (एजेंसी): सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी क्षेत्र) के क्रियान्वयन और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में किया गया है जब सरकार द्वारा अब तक करीब 15 लाख घरों का निर्माण कराया गया जबकि इस योजना के तहत 2015 से 2022 के बीच करीब एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह पुरस्कार तय अवधि के भीतर लाखों लोगों के घर के सपने को साकार करने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। मंत्रालय के मुताबिक, निर्माण, सामुदायिक गतिशीलता, झुग्गी पुनर्विकास, नीतिगत पहल, परियोजना निगरानी समेत अन्य में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए कुछ विशेष श्रेणी के पुरस्कार भी रखे गए हैं।

राजधानी में 17 लाख नए घरों का रास्ता हुआ साफ

लैंड पूलिंग पॉलिसी : 5 लाख घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत बनेंगे | बिल्डरों के साथ मिलकर डीडीए 5 जोन में फ्लैट तैयार करेगा | दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद : पुरी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली में 17 लाख नए घरों का रास्ता साफ हो चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब इस योजना के क्रियान्वयन पर काम शुरू करेगा। 6 सितंबर को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत डीडीए के पास 6 हजार हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है। अब बिल्डरों के साथ मिलकर डीडीए दिल्ली के 5 जोन में इस भूमि पर फ्लैट तैयार करेगा। सड़क और पानी जैसी बुनियादी सेवाएं डीडीए उपलब्ध कराएगा, जबकि अन्य इमारती ढांचा प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार होगा। 17 लाख में से 5 लाख घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार को ये जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने फिक्की सभागार में आयोजित सम्मेलन में दी। सम्मेलन में राजधानी के तमाम बिल्डरों को डीडीए ने आमंत्रित किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्डरों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्राधिकरण के साथ कार्य करने के लिए बढ़ावा देना था। इस दौरान एलजी अनिल बैजल भी मौजूद रहे।

डीडीए के वाइस चेयरमैन तरुण कपूर ने बताया कि 6 सितंबर को इस पॉलिसी के तहत आवेदन का आखिरी दिन था। इस योजना के तहत 6 हजार हेक्टेयर भूमि के आवेदन प्राधिकरण को मिले हैं। जल्द ही इन स्थानों पर आगे का कार्य शुरू होगा।

उन्होंने बताया कि 11 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचित लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली में पांच जोन एन, पी-2, के-1, एल और जे तय किया गया था। इसके तहत भू-स्वामी जमीन का पूल बना सकते हैं और उसे मास्टर प्लान के तहत विकसित कर सकते हैं। इसमें दिल्ली के करीब 95 गांवों का समावेश है। आरंभ में इस योजना को लेकर कई परेशानियां देखने को मिल रही थीं, लेकिन जब डीडीए ने गांवों में जाकर किसानों के बीच योजना के सही मायने समझाने का प्रयास किया, तो किसानों की दिलचस्पी बढ़ी। सम्मेलन में डीडीए ने बिल्डरों के तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्हें घाटे और मुनाफे के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में योजनाओं की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। अमर उजाला

मेट्रो फेज-4 के बचे तीन कॉरिडोर को मंजूरी जल्द

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले अगले कुछ महीनों में सरकार दिखाएगी झंडी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अगले कुछ महीनों में मेट्रो फेज-4 के रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर को सरकार की मंजूरी मिल जाएगी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शुक्रवार सुबह मेट्रो फेज-4 के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी बेहतर तरीके से लागू करने के लिए आवाजाही दुरुस्त करनी होगी। नरेला इलाका भी इसमें से एक है, जो मेट्रो फेज-4 के मंजूर किए गए तीन कॉरिडोर से नहीं जुड़ता, लेकिन सरकार अगले कुछ महीनों में जल्द ही इस कॉरिडोर को मंजूरी दे देगी। गौरतलब है कि 103.94 किमी लंबे दिल्ली मेट्रो के फेज-4 में छह कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। बीते साल 9 मार्च को इसमें से तीन कॉरिडोर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे रखी है। इसमें से एयरोसिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी (पश्चिम) और मुकुंदपुर से मौजपुर को करीब 24.95 हजार करोड़ में पूरा किया जाएगा, जबकि इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक व रिठाला-बवाना-मुंडका प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलनी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर नरेला कॉरिडोर को मंजूर कर लिया जाता है तो इलाके की आवाजाही आसान हो जाएगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी दिशा मिलेगी, यह सबके लिए फायदेमंद होगा। ब्यूरो

6,407 हेक्टेयर जमीन का पंजीकरण पूरा

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि डीडीए के पास 6,407 हेक्टेयर जमीन का पंजीकरण हो गया है। जोन पी-2, एन, एल एवं के-1 में किसानों ने क्रमशः 1,248 हेक्टेयर, 3,268 हेक्टेयर, 229 हेक्टेयर व 1,691 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत कराई है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर कई बार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि सरकार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी का रूप देने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2021 तक एफएआर को बढ़ाकर दिल्ली में बेहतर आवासीय योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं डीडीए दिल्ली में हरियाली को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है।

एनसीआर बोर्ड बैठक में मिली मास्टर प्लान 2021 को मंजूरी

एनसीआर के शहरों के समेकित विकास पर जोर, 2041 के मास्टर प्लान पर चर्चा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में एनसीआर के शहरों के लिए मास्टर प्लान-2021 को मंजूरी दे दी गई। वहीं प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर का दायरा बढ़ाने पर औपचारिक मुहर लगा दी है। विस्तारित क्षेत्रों में हरियाणा, राजस्थान के उप क्षेत्रों पर भी विचार किया गया। इसके अलावा पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर एनसीआर में पटियाला-राजपुरा कॉरिडोर को काउंटर मैगनेट क्षेत्र के रूप में शामिल करने पर स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश के शामली और मुजफ्फरनगर को भी एनसीआर के उप क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।

शुक्रवार शाम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, यूपी के मंत्री सिद्धार्थ सिंह, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन व राजस्थान सरकार के मंत्री शांति कुमार धारीवाल समेत सभी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजना को लागू करने के लिए मास्टर प्लान-2021 में वित्तीय सहायता देकर इन इलाकों को बेहतर किया जाएगा। पुरी ने एनसीआर का दायरा बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि मास्टर प्लान 2041 पर भी अभी से काम शुरू कर दिया गया है। अब तक के मास्टर प्लान की त्रुटियों को दूर करने के लिए समीक्षा कर संशोधन भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए यूपी में हाईटेक टाउनशिप, इंटीग्रेटिड टाउनशिप, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जेवर में प्रस्तावित हवाई अड्डे आदि से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाए। ब्यूरो

एक्सप्रेस वे से सफर बेहतर हुआ

यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय योजना-2021 एवं उत्तर प्रदेश उपक्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित इस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का क्रियान्वयन हो चुका है। इससे न सिर्फ आवाजाही बेहतर हुई है, बल्कि दिल्ली में वाहनों का दबाव भी कम हुआ है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के पूरा होने के बाद एनसीआर के यूपी के हिस्से वाले शहर भी नजदीक आएंगे। यह एक्सप्रेस वे उत्तराखंड का संपर्क भी बेहतर करेगा।

फल-सब्जी मंडी को किया जाए अन्यत्र स्थापित

बैठक में कहा गया कि दिल्ली से थोक व्यापार से संबंधित क्रियाकलापों को दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसके तहत कैमिकल पदार्थ, फल एवं अन्य पदार्थों के व्यवसाय को उत्तर प्रदेश के उपक्षेत्र के हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, खुर्जा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

...य संजय सिंह ने आरोप लगाया ... डॉ. हर्षवर्धन ने हरियाणा और

...का बेटा कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि यह इस बात को सत्यापित करता है कि भाजपा दिल्ली

...कौन है? उनकी पार्टी के अन्य सदस्य जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं वह सब कौन हैं?

...तंकी कहे ...गी मुद्दा

...ने पूछा जाएगा कि क्या ...ल आतंकवादी हैं?

...र्थक हाथों पर काले ...धकर करेंगे प्रदर्शन

...जवाब में मुख्यमंत्री ने ...ायोजित की थी और ...लोगों से यह तय करने ...हा था कि क्या वह ...बेटे हैं, एक भाई हैं या ...वादी हैं।

आम आदमी पार्टी का कहना है ...के पार्टी ने भाजपा ...टिप्पणी के खिलाफ ...ध दिखाने के लिए ...विधियों का संचालन ...फ़ला किया है। विरोध ...ाप के समर्थक हाथों ...बन बांधेंगे। इसके ...ता के बीच पर्चे भी ...। अगले कुछ दिनों ...ल्ली के मतदाताओं ...लकर उन्हें भाजपा ... दिल्ली की जनता ... करने के संबंध में ...ा ही पार्टी मुख्यमंत्री ...त्रे और आप सरकार ... को जनता के बीच ... के नेताओं की ...। जनता से अपील ...र वह केजरीवाल ...दी नहीं मानते तो झाडू को वोट करें।

...or more details visit
www.sunresolution.in /
www.eauctions.co.in or contact
CA Ramachandra D. Choudhary
Liquidator of Anil Limited
Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00157/2017-18/10326
rdc_rca@yahoo.com • 079 – 26566577 / 588

Toll-Free Helpline No.
1800-121-00-00-55
24 घण्टे* के अन्दर शुरूआती राहत पाये
A Quality Product by :
GOPAL LIFESCIENCES
AN ISO 9001:2015, GMP & GLP Certified Co.

जल्दी करें!

पहले आओ, पहले पाओ

आधार पर आबंटन

NBCC HEIGHTS SECTOR 89 GURUGRAM

एनबीसीसी हाइट्स

सेक्टर-89, गुरुग्राम

मेन पटौदी रोड पर स्थित

आपकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद

आवासीय फ्लैटों की बिक्री आरंभ

क्र.स.	विवरण	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V	टाइप-VI
1.	आवास का साइज़ (कनफिग्रेशन)	3 बीएचके	3 बीएचके+स्टडी		4 बीएचके+स्टडी	4 बीएचके+सर्वेन्ट
	बाल्कनी के अलावा कार्पेट एरिया (वर्ग फीट)	1148	1397		1638	1638
2.	सुपर एरिया (वर्ग फीट) 1 वर्ग मीटर =10.764	1752	2125		2458	2462

*पीएलसी एवं अन्य लागू शुल्क अतिरिक्त

1 वर्ग मीटर=10.764 वर्ग फीट

एनबीसीसी NBCC
नवरत्न सीपीएसई

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
विपणन कार्यालय:
एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली–110003

फोन करें:
011-46990020, 8527136569, 8527559481
ई–मेल: repre@nbccindia.com
विवरण के लिए वेबसाइट: www.nbccindia.com देखें
फॉलो करें:

स्थान
- 15 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट एवं 12 मीटर चौड़ी सर्विस रोड सहित (ज़ोनिंग प्लान के अनुसार) 75 मीटर चौड़ी पहुंच सड़क (पटौदी रोड)
- एन.एच. 8 एवं द्वारका एक्सप्रेसवे से आसानी से पहुंचने योग्य
- निवासियों के लिए सुविधाजनक दुकानें एवं नर्सरी स्कूल

- CC Division, NBCC

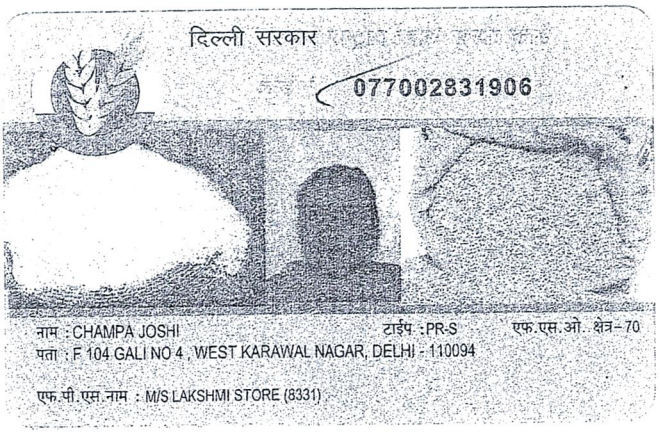

दिल्ली सरकार

077002831906

नाम : CHAMPA JOSHI टाईप : PR-S एफ.एस.ओ. क्षेत्र – 70

पता : F 104 GALI NO 4 , WEST KARAWAL NAGAR, DELHI - 110094

एफ.पी.एस.नाम : M/S LAKSHMI STORE (8331)

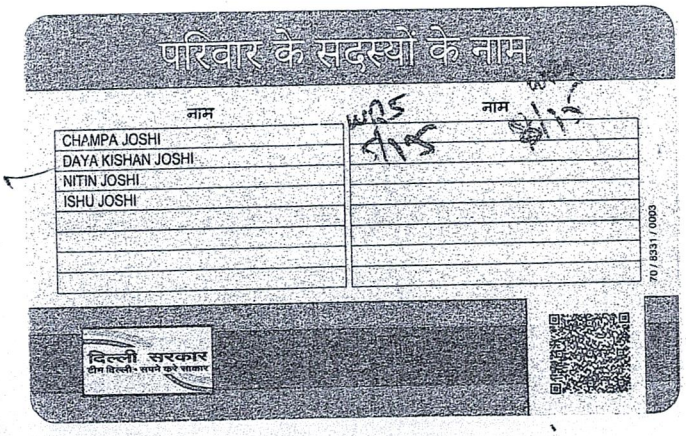

परिवार के सदस्यों के नाम

नाम	नाम
CHAMPA JOSHI	
DAYA KISHAN JOSHI	
NITIN JOSHI	
ISHU JOSHI	

70 / 8331 / 0003

दिल्ली सरकार
टीम दिल्ली • सपने करे साकार

प्रमाणित
BPL EWS Category
दयाकिशन जोशी
28/02/2020